DIMENSIONS IN INDIAN HISTORY

Edited by

A.K. SINHA

44. 1857 की क्रान्ति में आदिवासी जमीदारी सोनाखान के वीर नारायण सिंह की भूमिका 348
– *कविता श्रीवास्तव*
45. बंगाल का संन्यासी आंदोलनः संन्यासी आंदोलन या कृषक विद्रोह 358
– *अशोक त्रिपाठी*
46. 1857 के विद्रोह में साम्प्रदायिक एकता 366
– *नरेंद्र सिंह*
47. सती प्रथा तथा राजा राममोहन रॉय–पुनरावलोकन 374
– *ऋचा वर्मा*
48. उन्नीसवीं शताब्दी में उत्तरांचल का व्यापार एवं वाणिज्य 384
– *किरन त्रिपाठी एवं ज्योति साह*
49. किसान-असन्तोष एवं कांग्रेस (1928-1932) 393
– *अपर्णा*
50. 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में क्रान्तिकारी आन्दोलन और उसकी वैचारिक व्याख्या 400
– *रीनू जैन*
51. प्रथम स्वातन्त्र्य समर के पश्चात 1920 तक सामाजिक, राजनैतिक, बौद्धिक गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में मेरठ 420
– *सुधा शर्मा*
52. कुमाऊं में किसान आन्दोलन : सन 1927 से 1947 तक 427
– *ज्योति साह*
53. प्रेमचन्द के उपन्यास साहित्य में स्त्री विमर्श 435
– *महेन्द्र प्रताप एवं शुभ्रा सिंह*
54. पडरौना में 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन 441
– *मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं चन्द्रभूषण गुप्त*
55. समाचार पत्र 'आज' का स्वाधीनता संग्राम में योगदान 446
– *आराधना*
56. चमार जाति में संस्कृतिकरण का बदलता स्वरूप (जनपद मऊ के विशेष सन्दर्भ में) 459
– *राम विलास भारती*
57. वैश्वीकरण के दौर में हिन्दी सिनेमा : नई प्रवृत्तियां 466
– *चन्द्र भूषण गुप्त 'अंकुर'*

48. उन्नीसवीं शताब्दी में उत्तरांचल का व्यापार एवं वाणिज्य

किरन त्रिपाठी एवं ज्योति साह

1815 में गोरखों को पराजित करने के उपरांत सिगौली की संधि से कुमाऊं तथा गढ़वाल को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया गया और एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ।[1] वर्तमान देहरादून जिले का भूभाग मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत सहारनपुर जिले के साथ संयुक्त किया गया।[2] मंदाकिनी और अलकनंदा का पश्चिमी भाग (वर्तमान उत्तरकाशी और टिहरी जिले) राजा सुदर्शनशाह को प्रदान किया गया। सुदर्शनशाह ने भागीरथी और भिलंगना नदियों के बाएं तट पर स्थित टिहरी नामक छोटे से गांव को अपनी राजधानी बनाया।[3]

प्रशासनिक पुनर्गठन के साथ ही इस क्षेत्र के व्यापार तथा वाणिज्य में भी पर्याप्त सुधार हुआ। इस युग में व्यापार की प्रमुख विशेषताएं थीं—भोटांतिक व्यापार ग्रीष्मकाल में अल्मोड़ा, श्रीनगर, बागेश्वरर, रानीखेत आदि क्षेत्रों से होता था। जुलाई, अगस्त तथा सितंबर में तिब्बत के साथ व्यापारिक आदान-प्रदान चलता था। नवंबर के मध्य से वर्षाकाल के आरंभ तक अल्मोड़ा-टनकपुर-नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधियां तेज रहती थीं। पहले यह व्यापार बरमदेव मंडी तथा झूलाघाट के माध्यम से होता था, परंतु बरमदेव मंडी के बाढ़ में बह जाने के बाद इसका स्थान टनकपुर ने ले लिया।

सीमांत क्षेत्रों को बर्फ के कारण जून के अंत तक पार करना आसान नहीं होता था। नीती और माणा का मार्ग जून से अक्तूबर के अंत तक खुलता था। ब्रिटिश भूक्षेत्र तथा तिब्बत के बीच जुलाई से सितंबर तक की व्यापारिक अवधि में प्रत्येक व्यक्ति तीन या चार से अधिक यात्राएं नहीं कर पाता था। परंपरानुसार प्रत्येक भोटांतिक का व्यापारिक आदान-प्रदान तिब्बत में केवल एक ही आढ़ती के साथ होता था और तिब्बती व्यापारी को अपने उस आढ़ती या मित्र के अलावा किसी अन्य के साथ व्यापारिक संबंधों की अनुमति नहीं थी।[5] तिब्बत में इस व्यापार के प्रमुख केंद्र गढ़तोक, ज्ञानिमा, खिमलिंग, तकलाकोट तथा दारचन थे।[6] ब्रिटिश क्षेत्र से गर्ब्यांग भी इस व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। यहां से तकलाकोट

52. कुमाऊं में किसान आंदोलन सन 1927 से 1947 तक

ज्योति साह

ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध भारतीय किसानों का संघर्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश शासन के आरंभ से ही कई आंदोलनों की मुख्य शक्ति किसान ही थे।[1] क्षेत्रीय स्तर पर भी 20वीं सदी में कुमाऊं के अधिकांश आंदोलन किसानों की सक्रियता के ही परिणाम थे। इस सदी के प्रारंभिक दशकों में होनेवाले कुली-बेगार आंदोलन और वनांदोलन किसानों के प्रारंभिक सफल आंदोलन थे।[2] आगे के वर्षों में दोनों ही आंदोलन से किसान ऊर्जा प्राप्त करते रहे। इन आंदोलनों के दौरान ही किसान राष्ट्रीय संग्राम से जुड़ चुके थे।

सन 1927 से 1947 तक के वर्षों में भी कुमाऊं के किसानों ने शोषण के खिलाफ तीव्र प्रतिरोध जारी रखा। इस अवधि में किसानों की अपनी समस्याओं से जुड़े दो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए—पहला सल्ट का आंदोलन था, जो सन 1930-31 के राष्ट्रवादी आंदोलन का ही एक हिस्सा था, जबकि दूसरा अस्कोट का आंदोलन विशुद्ध रूप से भूमिहीन किसानों का आंदोलन था। इन दोनों आंदोलनों को इस दौरान होने वाले देशव्यापी किसान आंदोलन के क्रम में देखा जा सकता है। सन 1927 से 1947 तक किसान आंदोलन का विस्तार से वर्णन करने से पूर्व कुमाऊं की तत्कालीन कृषि व्यवस्था पर सामाजिक और आर्थिक दबावों का विश्लेषण करना आवश्यक है।

कुमाऊं में औपनिवेशिक काल भू प्रबंध की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। शासन के प्रारंभिक आठ दशकों में हुए भूमि बंदोबस्तों से 20वीं सदी के भू प्रबंध का स्वरूप निर्मित हुआ।[3] गोरखा शासन के सामंती दौर में भू स्वामित्व के शासक से जुड़े होने के बाबजूद भूमि तथा प्राकृतिक संपदा पर स्थानीय किसानों के सामुदायिक अधिकार थे। अंग्रेजों ने कृषि भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को महत्व दिया, परंतु गैर कृषि क्षेत्रों को राज्य स्वामित्व के अंतर्गत ले लिया। वास्तव में ब्रिटिश सरकार कृषि भूमि प्रबंध को व्यवस्थित करके ब्रिटिश अधिकार को स्थायित्व देना चाहती थी। इसलिए उसने परंपरागत थातवानी के स्थान पर हिस्सेदारी प्रथा